राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, बुधवार, 22 अप्रैल 2026

वर्ष 14, अंक 13, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

महमूदाबाद ब्लॉक परिसर में भाकियू (टिकैत) का जोरदार प्रदर्शन..03

न्यूजीलैंड-कनाडा मैच में हुई थी फिक्सिंग, कप्तान पर लगा आरोप ..04

विपक्ष का आचरण नारी गरिमा के प्रतिकूल, आक्रोशित महिलाएं दे रहीं सड़कों पर जवाबः सीएम योगी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को लोकसभा में विपक्ष द्वारा पारित नहीं होने देने के विरोध में मंगलवार को राजधानी लखनऊ ऐतिहासिक जनाक्रोश का साक्षी बना, जब महिला अधिकार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं सड़क पर उतरे। उनके नेतृत्व में हजारों महिलाओं का हुजूम मुख्यमंत्री आवास से सिविल हॉस्पिटल होते हुए विधान भवन तक उमड़ पड़ा। इस जनाक्रोश पदयात्रा में सीएम योगी के साथ पूरा मंत्रिमंडल सड़क पर उतरा दिखाई दिया। यह कोई साधारण पदयात्रा या रैली नहीं थी, यह नारी सम्मान और उसके संवैधानिक अधिकारों पर हुए हमले का सीधा और बेहद तीखा जवाब था।

सीएम आवास से विधानसभा तक निकली रैली

विधान भवन के सामने महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को विधानसभाओं एवं लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है, किंतु कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके सहित इंडी गठबंधन के दलों द्वारा इसे बाधित करने का प्रयास उनके अलोकतांत्रिक और महिला-विरोधी चेहरे को उजागर करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इन दलों को अपनी नकारात्मक छवि सुधारने का अवसर दिया गया था, किंतु इन्होंने उसका दुरुपयोग करते हुए महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी अन्याय के विरोध में देशभर में आधी आबादी सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक ढंग से अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। लखनऊ में प्रचंड गर्मी के बावजूद हजारों की संख्या में मातृशक्ति की सहभागिता प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के प्रति व्यापक जनसमर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। उन्होंने उपस्थित महिलाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश का एक-एक नागरिक आधी आबादी की इस न्यायोचित मांग के साथ मजबूती से खड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते वर्षों में देश ने व्यापक परिवर्तन देखा है, जिसमें 'महिला, गरीब, युवा और किसान' इन चार जातियों को केंद्र में रखकर नीतियों का निर्माण किया गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप देश ने विकास और आत्मनिर्भरता के नए मानक स्थापित किए हैं।

'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ', प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना सहित अनेक योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। स्वच्छ भारत मिशन केवल स्वच्छता का अभियान नहीं, बल्कि नारी गरिमा की रक्षा का सशक्त माध्यम है, वहीं उज्ज्वला योजना केवल ईंधन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और स्वावलंबन को सुदृढ़ करने का माध्यम है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं केवल लाभ वितरण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि परिवारों को स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर करने का सशक्त आधार बन रही हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, घरौनी वितरण जैसे प्रयासों ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक सशक्तीकरण से जोड़ने का कार्य किया है। डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य कर रही है, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के दल हर योजना का विरोध करते हैं।

डबल इंजर सरकार में महिलाओं की सुरक्षा हुई- योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने वाला है और यह व्यवस्था वर्ष 2029 तक लागू हो जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने सभी को आश्वस्त भी किया, इसके बावजूद इन विपक्षी दलों का जो आचरण रहा है, वह नारी गरिमा के प्रतिकूल रहा है। इसी कारण आज देशभर की महिलाएं इन दलों के विरोध में एकजुट होकर आंदोलन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 'डबल इंजन' सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना तथा युवा संबंधी अन्य योजनाएं इस दिशा में प्रभावी माध्यम बन रही हैं। मुख्यमंत्री ने आक्रोश पदयात्रा में बड़ी संख्या में सहभागिता के लिए सभी महिलाओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

तेज धूप भी नहीं रोक सकी संकल्प, हाथों में तख्तियां-होंठों पर प्रतिकार

पूर्वाह्न लगभग 10 बजे मुख्यमंत्री आवास से प्रारंभ हुई इस पदयात्रा के समय भी चुभने वाली तेज धूप थी, लेकिन महिलाओं का आक्रोश उससे कहीं अधिक धधक रहा था। हाथों में विपक्ष की कुत्सित राजनीति की निंदा करते हुए स्लोगन लिखी हुई तख्तियां और 'बहन- बेटियों का अपमान-नहीं सहेगा हिन्दुस्तान, महिला अधिकारों पर वार-सपा-कांग्रेस जिम्मेदार, कांग्रेस का हाथ-नारी शक्ति के खिलाफ, नारी के सम्मान में-एनडीए मैदान में' जैसे गूंजते नारों के साथ यह रैली विपक्ष की कायरता और राजनीतिक स्वार्थ को बेनकाब करती हुई आगे बढ़ी। हर कदम पर महिलाओं का हुजूम साफ संदेश दे रहा था- आधी आबादी के सम्मान और अधिकारों पर कोई समझौता नहीं, कोई चुप्पी नहीं, कोई माफी नहीं। जनाक्रोश पदयात्रा में हजारों महिलाओं की सहभागिता ने साबित किया कि आधी आबादी इस मुद्दे पर खामोश नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पदयात्रा में केन्द्रीय मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक और सहयोगी दलों के नेता सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा भाजपा की विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारियों के साथ अग्रिम पंक्ति में चल रहे थे। राजधानी लखनऊ के लिए यह एक अभूतपूर्व दृश्य था। रैली के दौरान पूरे मार्ग पर अनुशासन और उत्साह का अद्वितीय संगम देखने को मिला। युवा, वृद्ध, छात्राएं और कामकाजी महिलाएं, हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी ने इस आयोजन को व्यापक सामाजिक आधार प्रदान किया। जगह-जगह आम जनता ने भी तालियों और नारों के साथ इस पदयात्रा का समर्थन व स्वागत किया। महिलाओं ने सपा और कांग्रेस के विरुद्ध नारेबाजी की और विपक्ष की महिला-विरोधी मानसिकता को खुलकर चुनौती दी।

सबरीमाला केसः भेदभाव पर SC का अहम सवाल, क्या संविधान वंचितों की रक्षा नहीं करेगा?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछते हुए कहा कि अगर कोई श्रद्धालु पूरे मन से मंदिर जाता है, लेकिन उसे मूर्ति छूने की इजाजत नहीं दी जाती, तो क्या संविधान उसकी रक्षा नहीं करेगा? यह सवाल कोर्ट ने सबरीमला मंदिर के मुख्य पुजारी से पूछा. कोर्ट इस समय केरल के सबरीमाला मंदिर समेत दूसरे धार्मिक स्थानों पर होने वाले भेदभाव की सुनवाई कर रहा है. खासकर, महिलाओं और कुछ खास समुदायों के लोगों को मंदिरों में आने या पूजा करने पर लगी पाबंदियों पर कोर्ट में सवाल उठाए जा रहे हैं. यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों वाली एक बड़ी संविधान पीठ कर रही है. इस पीठ में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और दूसरे जज शामिल हैं. यह पीठ यह तय करने की कोशिश कर रही है कि धार्मिक आस्था और संवैधानिक अधिकारों के बीच की सीमा कहां है।

पुजारी की तरफ से क्या कहा गया?

मंदिर के पुजारी की तरफ से वरिष्ठ वकील वी. गिरी ने दलील दी. उन्होंने कहाः

किसी भी मंदिर के नियम और रीति-रिवाज उस धर्म का अहम हिस्सा होते हैं।

जब कोई भक्त मंदिर जाता है, तो उसे वहाँ के देवता के गुणों को मानना ही पड़ता है।

भक्त का काम देवता के सामने झुकना होता है, उल्टा चलने का उसे अधिकार नहीं है।

तब जस्टिस अमानुल्ला ने पूछा ये सवाल

सुनवाई के दौरान जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला ने बहुत साफ शब्दों में पूछा, 'जब मैं मंदिर जाता हूं, तो मेरी पूरी आस्था होती है कि वह भगवान ही मेरा सिरजनहार है. मैं बिल्कुल साफ मन से जाता हूं, मेरे दिल में कोई गंदगी नहीं होती. लेकिन वहां जाकर मुझे बता दिया जाता है कि मेरे जन्म या मेरी जाति की वजह से मैं भगवान को छू नहीं सकता. तो बताइए, क्या संविधान मेरी मदद नहीं करेगा? ' जस्टिस ने आगे कहा कि भगवान और उसकी बनाई सृष्टि (इंसान) में कोई फर्क नहीं हो सकता. अगर भगवान ने सबको बनाया है, तो फिर किसी एक को छूने से कैसे रोका जा सकता है?

पुजारी के वकील ने जस्टिस का दिया जवाब

पुजारी के वकील ने कहा कि अगर किसी जाति या जन्म की वजह से किसी को पुजारी बनने से पूरी तरह रोका जाता है, तो उसका समाधान संविधान के अनुच्छेद 25(2)(ख) के तहत कानून बनाकर किया जा सकता है. यानी राज्य या कानून इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट यह जानना चाह रहा है कि क्या धार्मिक रीति-रिवाजों के नाम पर किसी श्रद्धालु को भेदभाव सहना पड़ेगा? क्या संविधान का संरक्षण सिर्फ कुछ लोगों के लिए है या हर उस इंसान के लिए है, जो ईमानदारी से पूजा करने मंदिर पहुंचता है? इस मामले की सुनवाई अभी जारी है. अब देखना होगा इसपर क्या आखिरी फैसला लिया जाएगा।

योगी आदित्यनाथ की पदयात्रा विपक्ष में बैठने का 'अभ्यास' है: अखिलेश यादव

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ- समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने वाले संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने के विरोध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पदयात्रा भाजपा के विपक्ष में बैठने का 'अभ्यास' है। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यादव ने कहा, ''यह पदयात्रा अभ्यास थी। यह दर्शाता है कि विपक्ष में बैठने पर उन्हें इसी तरह का आंदोलन करना होगा। यह पहली सरकार है जो सत्ता में रहते हुए विपक्ष के रूप में काम करने का अभ्यास कर रही है।''

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) समेत अन्य विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में रुकावट डालने का आरोप लगाते हुए लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग से विधान भवन तक मंगलवार को 'जनाक्रोश महिला पदयात्रा' निकाली। पदयात्रा के दौरान अपने संबोधन में उप्र के मुख?यमंत्री योगी आदित?यनाथ ने कहा, ''आज, हमारी बहनों के नेतृत्व में लखनऊ में 'जनाक्रोश मार्च' निकाला जा रहा है। यह मार्च देश में, विशेष रूप से 'आधी आबादी' के बीच, कांग्रेस, सपा, टीएमसी और द्रमुक के महिला-विरोधी रवैये के खिलाफ व्याप्त रोष का प्रतीक है।''

इस पदयात्रा के समाप्त होने के कुछ देर बाद ही सपा मुख्यालय में विभिन्न दलों से आए नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के बाद यादव ने अपने संबोधन में कहा, ''सुना है कि लखनऊ में पदयात्रा हो रही थी, लेकिन इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था।'' उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, ''और ये जो पदयात्रा थी वह अभ्यास है कि विपक्ष में रहकर ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा। यह पहली सरकार है जो सरकार में रहकर विपक्ष में रहने का अभ्यास कर रही है।'' यादव ने कहा कि इससे पहले शायद किसी सरकार ने अपने ही बनाए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा, जितना यह संघर्ष कर रही है।

तेज रफ्तार का कहर! कार को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मारी जोरदार टक्कर, मां-बेटे की मौत, 9 अन्य घायल

बदायूं के उघैती थानाक्षेत्र में मंगलवार तड़के बिजनौर हाईवे पर एक तेज गति कार के सामने से आ रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार देने से एक महिला और उसके तीन महीने के बेटे की मौत हो गई, जबकि नौ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) हिरदेश कुमार कठेरिया ने बताया कि ज्ञानी कोतवाली क्षेत्र के गांव बसोमा के कुछ लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली से इस्लामनगर थाना क्षेत्र के समदनगर गांव में रिश्तेदारी के 'भात' कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। उन्होंने बताया कि उधैती कस्बे के पास पहुंचते ही सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने ट्रॉली में सीधी टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली पलट गई और उसमें सवार सभी लोग सड़क पर गिर गए। उन्होंने बताया कि चीख-पुकार मचने पर स्थानीय लोग दौड़े और पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने बताया कि सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदायन ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बसोमा निवासी सुमन (24) पत्नी हरदीप और उसके तीन माह के पुत्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा इस दुर्घटना में घायलों के नाम शिवानी (14), माही (10), ज्योति (15), सुनीता (40), उमानदेही (32), खुशबू (26), जय देवी (60), वीर (45) और वर्षा (16) वर्ष बताये गये हैं।

संक्षिप्त ख़बरें

नाबालिग को वयस्क कैदियों के साथ रखना पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 5 लाख मुआवजा देगी यूपी सरकार

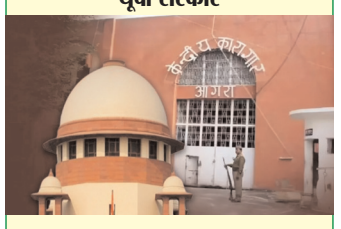

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले में कड़ी टिप्पणी की है, जहां एक नाबालिग को वयस्क कैदियों के साथ आगरा की केंद्रीय जेल में रखा गया था. अदालत ने इसे बाल संरक्षण कानूनों और संवैधानिक गारंटियों के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है. कोर्ट की फटकार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़ित नाबालिग को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है।

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला कानून से टकराने वाले बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने में सिस्टम की बड़ी नाकामयाबी है. पीठ ने कहा, 'यह एक ऐसा मामला है, जहां एक नाबालिग को नाबालिग घोषित किए जाने के बावजूद, अधिकारियों की ओर से संचार की कमी, असंवेदनशीलता और अमानवीय दृष्टिकोण के कारण गलत तरीके से वयस्क कैदियों वाली नियमित जेल में डाल दिया गया।

ऐसा करना कानूनी रूप से गलत

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी नाबालिग को वयस्क कैदियों के साथ रखना कानून के तहत पूरी तरह अस्वीकार्य है. अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की कैद बाल संरक्षण कानूनों और संवैधानिक गारंटियों के मूल सिद्धांतों पर गंभीर चोट है. सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यूपी सरकार तक सीमित रहने के बजाय पूरे देश के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को जारी किया है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस SOP को अन्य सभी राज्यों में भी भेजा जाए ताकि भविष्य में ऐसा कोई मामला न दोहराया जा सके. साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्य इसका पालन करें, अदालत इस मामले पर नजर बनाए रखेगी।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, घटना के दिन आरोपी नाबालिग था, फिर भी उसे वयस्क कैदियों के साथ आगरा केंद्रीय जेल में रखा गया था. यह घटना बाल संरक्षण कानूनों का गंभीर उल्लंघन मानी जा रही है. अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद पीड़ित को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है।

'मैं बोझ बन गया हूं...' नोएडा चाइल्ड PGI लैब में टेक्नीशियन ट्रेनी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा दर्द

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नोएडा सेक्टर 30 में मौजूद चाइल्ड पीजीआई में एक लैब टेक्नीशियन ने आत्महत्या कर ली. अपनी जीवनलीला समाप्त करने वाला युवक ट्रेनी था. उसने अपने कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान श्रावस्ती जिले के भिनगा गांव निवासी अवधेश कुमार के रूप में हुई है. वह चाइल्ड पीजीआई में लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग ले रहा था और अस्पताल परिसर में ही रह रहा था. सोमवार देर रात करीब 11 बजे वह अपने कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला. सुबह जब वह अपने कमरे से काफी देर तक बाहर नहीं निकला, तो अन्य दोस्तों ने उसके कमरे में जाकर देखा. कमरा अंदर से बंद था, जिसके बाद इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी गई।

कमरे में मिला सुसाइड नोट

अस्पताल प्रबंधन के लोग जब कमरे के पास पहुंचे, तो उन्होंने किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर देखा. वह पंखे से लटका हुआ था. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई. जांच के दौरान मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला. पुलिस के मुताबिक, सुसाइड नोट में युवक ने लिखा कि वह खुद को बोझ महसूस कर रहा है और किसी को परेशान नहीं करना चाहता. उसने यह भी लिखा कि वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाया और इस बात से बेहद दुखी था. सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के भी संकेत सामने आए हैं।

तीन दिन पहले ही छोड़कर गए थे परिजन

जानकारी के अनुसार, अवधेश के परिजन उसे करीब तीन दिन पहले ही पीजीआई परिसर में छोड़कर गए थे. घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. बताया जा रहा है कि युवक पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था, लेकिन उसने अपनी परेशानी किसी से खुलकर साझा नहीं की. इस मामले में पुलिस गहराई से जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या नौकरी और निजी जीवन से जुड़ा कोई दबाव इस आत्महत्या की वजह तो नहीं बना. थाना प्रभारी सेक्टर 20 का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुसाइड नोट की जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी।

कानपुर की भगवत गैस एजेंसी में उपभोक्ताओं का हंगामा, सिलेंडर वितरण में धांधली और वसूली का आरोप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर। शहर के जेके टेंपल के नजदीक स्थित भगवत गैस एजेंसी विवादों का अड्डा बन गई है। जबसे युद्ध की स्थितियां चल रही हैं, तबसे यहां सिलिंडर का वितरण कम, उपभोक्ताओं और संचालक के बीच विवाद ज्यादा होता है। सोमवार को एजेंसी में उपभोक्ताओं के बवाल के बाद दूसरे दिन मंगलवार की सुबह फिर से विवाद शुरु हो गया।

भगवत गैस एजेंसी में एक दिन पहले सोमवार को घरेलू गैस सिलिंडर लेने के लिए पांच सौ से अधिक लोग जमा हुए थे। मगर सिलिंडर सिर्फ 120 उपभोक्ताओं को ही मिल सका था। शेष उपभोक्ताओं को दोपहर दो बजे दूसरा स्टाक आने के बाद वितरण करने का आश्वासन दिया गया था। मगर तीन बजे तक लाइन में लगे रहने के बावजूद जब गैस नहीं मिली तो उपभोक्ताओं ने हंगामा कर दिया था। ग्राहकों ने गैस सिलिंडरों की लाइन लगाकर सड़क जाम करने का भी प्रयास किया था। मंगलवार को अगले दिन जब गैस लेने एकत्र हुए तो वितरण को लेकर फिर से समस्या खड़ी हो गई। सुबह नौ बजे से लाइन में लगे लोगों को साढ़े दस बजे तक जब सिलिंडर नहीं मिली तो लोगों ने हंगामा करना शुरु कर दिया। लोगों ने सवाल उठाया कि एक दिन पूर्व देर शाम आए स्टाक का क्या हुआ, किसे और कब दे दिए गए।

उपभोक्ताओं ने बताया कि संचालक सवाल पूंछने पर सही जवाब नहीं देते, उपभोक्ताओं से केवाईसी के नाम पर दो से ढ़ाई सौ रूपए लिए जा रहे हैं, सिलिंडर मिलने पर एक पाइप और चाय की पत्ती लेने का दबाव बनाया जाता है। न लेने पर संचालक सिलिंडर न देने की धमकी देते हैं। वहीं इस संबंध में डीएसओ राकेश कुमार ने बताया कि लोड पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है, स्टाक की समस्या नहीं है। वितरण में देरी क्यों हुई इसकी जांच की जा रही है।

कानपुर रोडवेज कार्यशाला में चालक-परिचालकों का हंगामा, बस मरम्मत में कमीशनखोरी का आरोप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर। परिवहन निगम की विकास नगर कार्यशाला में मंगलवार को चालक-परिचालकों ने जमकर हंगामा काटा। हंगामा की सूचना पाकर कार्यशाला में क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार भी पहुंच गए थे। वह दोपहर 12:00 तक कार्यशाला में ही जम रहे। चालक परिचालकों को काफी समझाने का प्रयास किया। चालक-परिचालकों का आरोप है कि कार्यशाला में उनका आरोप है कि बसों की मरम्मत के नाम पर जमकर कमीशन खोरी की जा रही है। आरोप लगाया कि बसों में निम्न गुणवत्ता वाले उपकरण लगाया जा रहे हैं। बार-बार मरम्मत के बाद भी एसी चल रही है। गाड़ियों में ब्रेकडाउन हो जा रहे हैं। इससे गाड़ियां रास्ते से वापस लौट रही हैं। यही कारण है की बसें निर्धारित दूरी तय नहीं कर पा रही हैं। इससे परिवहन निगम का भी घटा हो रहा है।

चालक-परिचालकों ने बताया कि यूपी 78-एफटी-7596 एसी बस मंगलवार सुबह बनारस के लिए निकली थी, जो रामादेवी चौराहे से वापस लौट आई थी। बस करंट छोड़ रही थी, पिकअप नहीं ले पा रही थी। इस बस के चालक वीरेंद्र भदोरिया ने बताया कि उनकी गाड़ी कई बार कार्यशाला में पहले भी मरम्मत हो चुकी है, लेकिन उपकरण की गुणवत्ता बेहतर नहीं होने से बस में सुधार नहीं हो रहा है।

यूपी 78-एफटी-7595 बस में 2 महीने से एसी की कूलिंग खराब है। यह बनारस रूट की बस है जो मरम्मत के लिए कार्यशाला में खड़ी है। इस बस के चालक कैलाश दुबे ने बताया कि उन्हें धमकाया जा रहा है कि बस नहीं चलाओगे तो संविदा समाप्त कर दी जाएगी।

इसी तरह यूपी 78 एफएन 7424 एसी बस के चालक अनिल पांडे ने बताया कि उनकी गाड़ी रोज ब्रेकडाउन होती है। इंजन और एसी में काफी दिक्कतें हैं। इसलिए रूट पूरा करने में बड़ी मुसीबत रहती है। पैसेंजर भी झगड़ते हैं। चालक-परिचालकों ने यह भी बताया कि यह कार्यशाला पिछले डेढ़ साल पहले निगम ने प्राइवेट में जयपुर ऑटो रिपेयर सेंटर को ठेके पर दे दी थी। उसी के बाद से रोडवेज बसों में तमाम दिक्कतें दूर नहीं हो पा रही हैं, जबकि खर्चा दोगुना बढ़ा है। पहले महीने में कार्यशाला का खर्च 18 से 20 लाख रुपए तक आता था और आज 50 लाख रुपए से भी अधिक महीने का खर्च निकल रहा है और बसें अपना रूट पूरा नहीं कर पा रही हैं। करशाला में ठेके के कर्मचारी फोरमैन तक की सुनते नहीं है।

बनारस एक भी नहीं गई बस

कानपुर बनारस रोड पर एसी की पांच गाड़ियां संचालित हैं। इन बसों में तमाम दिक्कतों के कारण मंगलवार को एक भी गाड़ी बनारस के लिए नहीं गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक बोले, कार्यशाला में कोई हंगामा नहीं।

चालक-परिचालकों की समस्याओं और उनके हंगामे की बात को क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला ही नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला पर मैं बैठा हूं, कोई भी चालक-परिचालक हंगामा करने नहीं आया है।

तमिलनाडु की सियासत में बूथ की जंग: वोटर रिमाइंडर से बदला चुनावी मैदान, अस्मिता बनाम संगठन की टक्कर

तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां चुनावी जंग अब बड़े-बड़े मंचों और नारों से निकलकर सीधे बूथ स्तर तक पहुंच चुकी है। इस बार मुकाबला केवल पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि रणनीतियों, संगठन क्षमता और मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कला के बीच भी है। सत्तारूढ़ एम. के. स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने चुनावी लड़ाई को अंतिम चरण में एक नए आयाम पर ला दिया है, जिसे 'वोटर रिमाइंडर कैंपेन' के रूप में देखा जा रहा है। यह अभियान केवल मतदाताओं को मतदान की याद दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक-राजनीतिक संवाद का हिस्सा बन चुका है।

तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से एक चक्र चलता आया है, जिसमें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बारी-बारी से सत्ता में आती रही हैं। इस बार की सबसे बड़ी चुनौती इसी चक्र को तोड़ने की है। एम. के. स्टालिन के सामने यह केवल सत्ता में बने रहने का सवाल नहीं, बल्कि एक स्थायी राजनीतिक आधार तैयार करने की परीक्षा भी है। यही कारण है कि उनकी पार्टी ने प्रचार के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर मतदाताओं के दरवाजे तक पहुंचने की रणनीति अपनाई है।

'वोटर रिमाइंडर कैंपेन' दरअसल एक सूक्ष्म और लक्षित अभियान है, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। इस अभियान में विशेष रूप से महिलाओं, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। यह रणनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमिलनाडु के चुनावों में महिलाओं की भागीदारी और उनका झुकाव अक्सर निर्णायक भूमिका निभाता है। इसके साथ ही शहरी, तटीय और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ को मजबूत करने का प्रयास भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

दूसरी ओर, विपक्ष में खड़ी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अपनी पारंपरिक ताकत, यानी मजबूत बूथ संगठन और ग्रामीण नेटवर्क पर भरोसा कर रही है। एडापड्डी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व में पार्टी पश्चिमी तमिलनाडु के जिलों–कोयंबटूर, तिरुपुर, इरोड और सेलम–में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। यहां पार्टी का आधार मुख्य रूप से गौंडर समुदाय पर टिका हुआ है, जो लंबे समय से उसकी रीढ़ माना जाता रहा है। हालांकि, बदलते सामाजिक समीकरण और गठबंधन राजनीति ने इस बार इस समर्थन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के लिए दोधारी तलवार साबित हो रहा है। जहां एक ओर यह गठबंधन कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक मजबूती देता है, वहीं दूसरी ओर दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच पार्टी की स्वीकार्यता को प्रभावित कर रहा है। यही कारण है कि कई ऐसे क्षेत्र, जो पहले पार्टी के मजबूत गढ़ माने जाते थे, अब वहां स्थिति उतनी सहज नहीं दिख रही।

इस चुनाव में मुद्दों की बात करें तो केवल स्थानीय समस्याएं ही नहीं, बल्कि बड़े राष्ट्रीय और भावनात्मक विषय भी प्रमुखता से उभरे हैं। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन का मुद्दा, जिसे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने तमिलनाडु के अधिकारों से जोड़ दिया है, चुनावी बहस के केंद्र में है। पार्टी इसे 'राज्य बनाम केंद्र' के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जिससे क्षेत्रीय अस्मिता को बल मिलता है। इसके अलावा महिला कल्याण योजनाएं, नकद सहायता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वादे भी मतदाताओं को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

युवाओं के बीच भी इस बार चुनावी चर्चा काफी सक्रिय है। रोजगार, शिक्षा और विशेष रूप से ह्वश्वश्वज्ञ परीक्षा जैसे मुद्दे लगातार उठ रहे हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने इन मुद्दों को राज्य की स्वायत्तता और केंद्र के हस्तक्षेप से जोड़ते हुए अपनी राजनीतिक रणनीति को धार दी है। सोशल मीडिया पर भी पार्टी की सक्रियता इस बात का संकेत देती है कि वह युवा मतदाताओं तक पहुंच बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।

इसके साथ ही, तमिल सिनेमा और राजनीति का पारंपरिक संबंध भी इस चुनाव में नजर आ रहा है। अभिनेता विजय की राजनीतिक सक्रियता और उनके नए प्रयासों ने युवा मतदाताओं में एक अलग तरह की उत्सुकता पैदा की है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इसका सीधा लाभ किसे मिलेगा, लेकिन यह निश्चित है कि इससे चुनावी माहौल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

तमिलनाडु की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन इस बार उनका प्रभाव अपेक्षाकृत कम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। इसके बजाय 'अस्मिता', 'अधिकार' और 'कल्याण' जैसे व्यापक मुद्दे अधिक प्रमुखता से उभरकर सामने आए हैं। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि राज्य की राजनीति धीरे-धीरे एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जहां मतदाता केवल पारंपरिक पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस नीतियों और प्रदर्शन के आधार पर भी निर्णय ले रहे हैं।

चुनाव के इस अंतिम चरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़ाई अब पूरी तरह से बूथ स्तर पर सिमट गई है। कौन पार्टी अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में सफल होती है, कौन अपने मतदाताओं को अंतिम समय तक जोड़े रख पाती है–यही जीत और हार का निर्धारण करेगा। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का 'वोटर रिमाइंडर कैंपेन' और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का मजबूत बूथ नेटवर्क–इन दोनों के बीच की टक्कर इस चुनाव की असली कहानी बन चुकी है।

अंततः, तमिलनाडु का यह चुनाव केवल एक राज्य की सत्ता का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह उस दिशा का संकेत भी है, जिसमें क्षेत्रीय राजनीति आगे बढ़ रही है। क्या एम. के. स्टालिन इस बार सत्ता में वापसी कर इतिहास रच पाएंगे, या फिर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अपने संगठन के बल पर वापसी करेगी–यह तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बार की जंग ने तमिलनाडु की राजनीति को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है, जहां हर वोट, हर बूथ और हर मतदाता निर्णायक बन चुका है।

कांतिलाल मांडोत

ज्ञान, संस्कार और चरित्र से ही श्रेष्ठ समाज और राष्ट्र का निर्माण

विचार और सिद्धांत व्यक्ति के अंदर की अतः प्रज्ञा होती है। और यह सिद्धांत तथा अंतः विचारधारा जनमानस तक पहुंचने से बाधित किया जाए अंतरात्मा को प्रभावित करती है और इसके गहरे प्रभाव से व्यक्ति वह सब कर सकता है जो बिना मार्गदर्शन के व्यक्ति नहीं कर सकता। प्राचीन काल से अब तक वैचारिक सिद्धांत और विचारधारा सदैव समाज के दिग्दर्शक मार्गदर्शक रहे हैं। इनकी भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है।यदि यही सिद्धांत और अंतःप्रज्ञा जनमानस आत्मसात कर लेता है, तो इसका प्रभाव एक जन आंदोलन का रूप ले लेता है और यहीं से युग परिवर्तन की लहर प्रस्फुटित होती है। प्राचीन यूनान में एक बहुत ही कुरूप किंतु विद्वान व्यक्ति रहते थे,उनके विचारों में मौलिकता,नयापन जनजागृति की अद्भुत क्षमता थी। उनकी विद्वता के कारण आम जनमानस होने राजा से ज्यादा महत्व और बुद्धिमान मानते थे। राजकीय तानाशाही के चलते उनके विचारों के कारण उनको मृत्युदंड दे दिया गया। जहर का प्याला पीने के बाद भी विद्वान, चिंतक, सुकरात अमर हो गए, उनकी विचारधारा आज भी जीवित है, एवं लोग उसे अपनाकर अपना जीवन सुधारने में इसका उपयोग करते हैं। अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद दास प्रथा के बारे में कहा था कि दास भी मनुष्य हैं, उन्हें भी उतना ही जीने का अधिकार है जितना स्वामी को है। अब्राहम लिंकन के आंदोलनकारी विचार से तत्कालीन समय में अमेरिका के लोग घबरा गए थे,और उनकी हत्या कर दी गई थी। पर अब्राहम लिंकन के विचारों ने दास प्रथा के उन्मूलन की अंतर आत्मा को जागृत कर दिया था, और जनमानस ने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए दास प्रथा से मुक्ति पाई थी।

स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। विचार एवं सिद्धांत ही व्यक्ति का निर्माण करता है। वही दुष्ट होने या महान होने का निर्णायक है। और बिना विचारों सिद्धांतों के व्यक्त व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं । विवेकानंद जी के विचार सर्व कालीन प्रासंगिक है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उनके जीवित रहते हुए थे। आज हमारे बीच विवेकानंद जी स शरीर मौजूद नहीं है, पर उनके विचारों की महत्ता कायम है।भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने से और भौतिक विचार तथा सिद्धांत उतनी ही तीव्रता रखते हैं, वेग रखते हैं, जो एक समाज में परिवर्तन ला सकती है ।विचारों की यह अमरता तथा तीव्रता किसी भी तानाशाह के लिए इतनी खतरनाक है, जितनी की सुप्त शेर की गुफा में रहना। जनता के मध्य शुद्ध विचारधारा के जागृत होने पर क्रांति लाई जा सकती है। फिर चाहे वह फ्रांस के वर्साय के महल का विध्वंस हो अथवा भारत की स्वतंत्रता हेतु वृहद आंदोलन हो। व्यक्ति या व्यक्तियों के दबाव को दबाने के बाद विचारों की पीड़िता ने जनसामान्य को एक गरजते हुए सिंह में तब्दील कर दिया था। यह शाश्वत सत्य है कि व्यक्ति को जरूर आप दबा सकते हैं,पर विचारधारा सिद्धांत अजर अमर होते हैं,और वही युग निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाते हैं।

विचारों के संदर्भ में कहा जाता है कि एक व्यक्ति का विचार तब तक उस व्यक्ति के पास है, जब तक वह अकेला है किंतु जैसे ही विचारधारा एवं सिद्धांत का प्रचार प्रसार होता है, तो वह व्यक्ति अकेला ना रह कर उस जैसे हजारों लाखों लोग उसके साथ हो जाते हैं। तब वह अकेला नहीं रह जाता। वह अपने विचारों के माध्यम से जन सामान्य को प्रभावित कर लोगों को उस लड़ाई में शामिल कर लेता है, जिस लड़ाई के वह कभी अकेले नहीं लड़ सकता था। विचारों सिद्धांतों की तीव्रता आवेश तथा सघनता किसी भी क्रांतिकारी लक्ष्य की प्राप्ति में एक बड़ा साधक हो सकता है। विचार व सिद्धांत एक से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित होते रहते हैं। जिसमें विचारों को सघनता प्राप्त होती है। ताकि सत्ता के दमन के समय वैचारिक अमरता स्थाई बनी रहे। चीन उत्तर कोरिया जैसे राष्ट्रों में विचारों के इस स्वतंत्र का प्रवाह को बाधित नियंत्रित कर दिया गया। अभिव्यक्ति के तमाम माध्यमों को प्रतिबंधित कर दमन चक्र चलाया गया। वहां विचार और सिद्धांत विद्वान व्यक्ति तक ही सीमित रहे उसका फैलाव या विस्तार नहीं हो पाया। जो मानव समाज तथा मानव अधिकारों की संवेदना तथा धाराओं का उल्लंघन भी है।

किसी स्वस्थ,स्वतंत्र राष्ट्र के लिए व्यक्ति समाज और राष्ट्र के विचारों की स्वतंत्रता नवीनता तथा उत्कृष्टता अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि विचारधारा और सिद्धांतों को रोक पाना किसी भी सत्ता या निरंकुश राजा के नियंत्रण में नहीं होता। विचारों और सिद्धांत अनादि काल से गतिशील है तथा अनंत तक जगत तक गतिशील रहेंगे,और उसका प्रतिपादक एवं अनुशीलन कर्ता विचारों के साथ अमर हो जाते हैं।

संजीव ठाकुर

जब व्यवस्था बोलती है, तो नाम सिविल सेवकों का होता है

प्रशासन नहीं, परिवर्तन का विज्ञान: सिविल सेवा दिवस

फाइलों के पीछे की फौज: जो भारत को हर दिन चलाती है

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस उस अदृश्य शक्ति का उत्सव है जो देश की शासन व्यवस्था को गति, स्थिरता और दिशा प्रदान करती है। 21 अप्रैल को मनाया जाने वाला यह दिन उन सिविल सेवकों के योगदान को रेखांकित करता है, जो केवल प्रशासनिक पदों पर नहीं, बल्कि परिवर्तन के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ये अधिकारी योजनाओं को नीति-पत्रों से निकालकर समाज की वास्तविक जरूरतों से जोड़ते हैं और विकास को जमीनी स्तर पर जीवंत बनाते हैं। संकट की घड़ी हो या विकास की चुनौती, उनकी त्वरित निर्णय क्षमता और निष्ठा पूरे राष्ट्र को संतुलन और विश्वास देती है। यह अवसर हमें उनके मौन लेकिन प्रभावशाली योगदान को समझने और एक ऐसे प्रशासन के निर्माण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है, जो अधिक उत्तरदायी, संवेदनशील और जनकेंद्रित हो।

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का ऐतिहासिक आधार उतना ही प्रेरक है जितना इसका वर्तमान संदेश। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभभाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के प्रथम बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया था। उन्होंने उन्हें 'देश का स्टील फ्रेम' (स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया) कहा, जो एक मजबूत, निष्पक्ष और ईमानदार प्रशासन की राष्ट्र निर्माण में अनिवार्य भूमिका को दर्शाता है। उनका यह संदेश सिविल सेवकों के लिए निर्भीकता, निष्पक्षता और जनसेवा की स्पष्ट दिशा बन गया। यह दिवस उसी विचार को जीवंत करता है, जब प्रशासनिक सेवाओं के महत्व को पुनः स्मरण करते हुए उनके योगदान को सम्मान और कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया जाता है तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी निर्णायक भूमिका को और अधिक सशक्त करने का संकल्प लिया जाता है।

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का उद्देश्य सिविल सेवकों के योगदान को सम्मान देना ही नहीं, बल्कि उन्हें जनसेवा में अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनने की प्रेरणा देना है। इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/जिलों/संगठनों को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो उनके उल्लेखनीय प्रयासों और सफल क्रियान्वयन का सम्मान है। यह सम्मान न केवल उनकी मेहनत को मान्यता देता है, बल्कि पूरे प्रशासन तंत्र में बेहतर कार्य की प्रेरणा भी पैदा करता है। साथ ही यह दिन पारदर्शिता, जवाबदेही और जन-केंद्रित शासन को मजबूत करने का संदेश देता है, ताकि सरकारी योजनाएँ बिना बाधा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सकें।

भारत जैसे देश में, जहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता अत्यधिक है, सिविल सेवकों की भूमिका केवल प्रशासन तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्र की जीवनरेखा के समान है। वे नीतियों को लागू करने वाले साधारण कार्यकर्ता नहीं, बल्कि समानता, न्याय और सामाजिक सद्भाव के वास्तविक रक्षक हैं। विकास योजनाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचाना, वंचित और कमजोर वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करना तथा समाज को एकता के सूत्र में बाँधना–ये सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ उनके कंधों पर होती हैं। संकट के समय उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। चाहे कोविड-19 जैसी महामारी हो, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएँ हों या कोई अन्य राष्ट्रीय संकट, सिविल सेवक सदैव अग्रिम पंक्ति में रहकर देश को संभालते हैं। उनकी अटूट निष्ठा, समर्पण और कर्तव्यपरायणता ही भारत को हर कठिन परिस्थिति में स्थिरता और प्रगति की दिशा प्रदान करती है।

आज का समय तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल नवाचार का युग है, जिसने सिविल सेवकों की जिम्मेदारियों को पहले से अधिक व्यापक और जटिल बना दिया है। अब उन्हें पारंपरिक प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाकर शासन को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाना होता है। डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने ई-गवर्नेंस को मजबूत किया है, जिससे ऑनलाइन सेवाएँ, डिजिटल लेन-देन और सरल प्रक्रियाएँ जनता तक सुविधाजनक रूप से पहुँच रही हैं। साथ ही साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और डिजिटल जागरूकता जैसी नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। ऐसे में सिविल सेवकों का दायित्व है कि वे इन चुनौतियों का समाधान करते हुए प्रशासन को अधिक सक्षम, जन-केंद्रित और भविष्य उन्मुख बनाएँ, ताकि भारत एक सशक्त डिजिटल राष्ट्र के रूप में निरंतर आगे बढ़ सके।

आज सिविल सेवकों के सामने सामाजिक-आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय संकट और जनसंख्या वृद्धि जैसी गंभीर चुनौतियाँ हैं, जिनके लिए दीर्घकालिक और प्रभावी समाधान जरूरी हैं। इनसे निपटने के लिए नवाचार, सहयोग और दूरदर्शी सोच अपनाना आवश्यक है। आदर्श सिविल सेवक वही है जो निष्पक्षता, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ जनहित को सर्वोपरि रखे। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस इस विचार को मजबूत करता है और प्रशासन में सुधार, दक्षता और पारदर्शिता पर चिंतन का अवसर देता है। निरंतर प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता और मजबूत व्यवस्था से सिविल सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है तथा जन-केंद्रित दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रशासन वास्तव में जनता के हित में कार्य करे।

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस सिविल सेवकों के लिए आत्मचिंतन और कर्तव्यनिष्ठा को पुनः जागृत करने का प्रेरक अवसर है। यह दिन सरदार वल्लभभाई पटेल के उस विचार को फिर से सशक्त करता है, जिसमें उन्होंने निष्पक्षता, ईमानदारी और जनता के प्रति जवाबदेही को सुशासन की आधारशिला बताया था। इस अवसर पर सिविल सेवकों को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे देश, संविधान और नागरिकों के हित में पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करेंगे। उनकी यह निष्ठा ही भारत को मजबूत, समावेशी और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने में आधार बनती है। यह दिवस उनके योगदान को सम्मान देने के साथ यह विश्वास भी जगाता है कि सिविल सेवाएँ ही राष्ट्र की एकता और विकास की वास्तविक शक्ति हैं।

कृति आरके जैन

भारत में कभी शाश्वत नहीं रही अस्पृश्यता

वर्तमान भारत में अस्पृश्यता को लेकर कई प्रकार के विमर्श चल रहे हैं। एक विमर्श यह है कि भारत में उच्च वर्ग के लोगों ने निम्न वर्ग के साथ भेद - भाव किया। उन्हें पानी पीने, शिक्षा प्राप्त करने एवं समान व्यवहार के लिए वंचित किया गया। यह विमर्श सर्वथा झूठ और मन गठन्त कहानी और कुंठा से भरा हुआ है। सच तो यह है कि इस प्रकार की उच्च जाति व निम्न जाति का विषय भारत के लोगों द्वारा नहीं अपितु भारत में लम्बे समय तक हुए बाह्य आक्रमणों मुगलों व अंग्रेजों की देन है। जो कभी स्थाई नहीं रही। प्राचीन भारत में कभी जाति वैमनस्यता, घृणा, ऊंच नीच का भाव जनमानस में नहीं था। इसके उदाहरण हम आज भी अपने घरों में देखते है। जैसे जब हमारे घरों में वैदिक परंपरा से विवाह होता है तब उस विवाह को संपन्न कराने के लिए सर्व समाज जाति बिरादरी के लोगों का कार्य होता है उनके भाग के बिना विवाह के सारे कार्यक्रम सम्पन्न होना संभव ही नहीं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद भाव नहीं है। वहीं यदि सतयुग की बात करते हैं तो राजा हरिश्चंद्र आते हैं जो डोम के यहां नौकरी करते हैं कोई भेद भाव नहीं है। राजा बलि और भगवान वामन देव का उदाहरण कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार त्रेता युग में भगवान श्रीराम के जीवन से स्पष्ट होता है कि समाज कितना एक रस था। भीलनी के झूठे बेर खाने का प्रसंग, वनवासियों के साथ संगठन कर लंका विजय का प्रसंग, निषादराज को गले लगाना 'तुम मोहि प्रिय भरतहीं सम भाई' इत्यादि अनेकों उदाहरण समाज को एक साथ बिना किसी भेद के दर्शाते हैं। द्वापर में जब हम बात करते हैं तब भी समाज में कोई जातीय वैमनस्य अस्पृश्यता नहीं है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सारे भेदों से परे हैं। पांडवों का अज्ञातवास के समय अनेकों ऐसी घटनाएं मिलती है जहां कोई भेद भाव नहीं है। भीम और हिडम्बा का विवाह, राजा शांतनु का विवाह, विदुर के यहां भगवान का भोजन इत्यादि। महाभारत में बहुत सारे सहज समरसता के विषय मिल जाएंगे जो समाज में एकाकार को दर्शाते हैं अब हम कलियुग की बात करते हैं यहां भी कोई जातीय वैमनस्य नहीं है। मध्यकाल में भारत में हुए आक्रमणों से हिन्दू समाज में कुछ विकृतियां आई लेकिन कभी शाश्वत नहीं रही उन्हें दूर करने के लिए भारत में अनेकों संत, महात्माओं, मनीषियों, महापुरुषों ने समय समय पर समाज को दिशा प्रदान कर अभियान चलाया है। चाहे वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, राजा राममोहन राय, सन्त रविदास, गुरुनानक देव जी, मीराबाई, सन्त नामदेव जी, शिवा जी महाराज, महाराणा प्रताप, डॉ केशव बलीराम हेडगेवार, सावित्री बाई फुले, लोकमाता अहिल्याबाई होकलर आदि सैकड़ों नाम है जो भारत में बाहर से आई कुरीतियों को लेकर समाज में लम्बा संघर्ष किया। आज डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर के विषय को लेकर राजनैतिक लोग समाज में घृणा फैलान का कार्य करते हैं। डॉ अम्बेडकर ने कभी भी समाज को विभाजित करने की बात नहीं की उन्होंने भी संपूर्ण हिन्दू समाज को साथ रहने की वकालत की है। डॉ अम्बेडकर के जीवन में जब कभी ऐसी घटनाएं अस्पृश्यता की आई भी तो हमारे ही लोगों ने उनका विरोध किया और डॉ अम्बेडकर को आगे बढ़ाया। डॉ अम्बेडकर को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने वाले ब्राह्मण बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे। डॉ. भीमराव अंबेडकर को 'अंबेडकर' सरनेम उनके ब्राह्मण शिक्षक कृष्णाजी केशव अंबेडकर ने दिया था। स्कूल के रिकॉर्ड में उनका मूल उपनाम 'अंबावाडेकर' (गांव के नाम पर) से बदलकर शिक्षक ने अपना उपनाम 'अंबेडकर' रख दिया था। इसलिए भारत में जातीय घृणा का सिद्धांत कभी नहीं रहा है। मेरा सभी से आग्रह है कि भारत को जानो, भारत को मानो और भारत के बनो। किसी भी पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए स्वच्छ मन मस्तिष्क से भारत के ग्रंथों का अध्ययन करें। भारतीय वांग्मय में भी कहीं पर घृणा, उन्मूलन का संदर्भ नहीं है बस शास्त्रों का अध्ययन उनकी व्याख्या मनमाने ढंग से करने से बचें परम्परा से प्राप्त ज्ञान के आचार्यों से मिलकर अध्ययन करें सबकुछ समझ में आयेगे। डॉ अम्बेडकर का मत भी है कि सबके साथ समान व्यवहार, समान शिक्षा, समान सम्मान। खूब पढ़ो, परिश्रम करो, सफलता प्रदान करो आरक्षण की वैशाखी से बाहर निकले।

बाल भास्कर मिश्र

जलती धरती पर करुणा की छांव: प्यासे परिंदों के लिए इंसानियत का सबसे सुंदर अभियान

भीषण गर्मी जब अपने चरम पर होती है, तब सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर जीव-जंतु उसके प्रभाव से जूझता है। जहां मनुष्य अपने लिए ठंडे पानी, पंखे, कूलर और एसी का इंतजाम कर लेता है, वहीं आकाश में उड़ने वाले छोटे-छोटे पक्षी, गिलहरियां और अन्य अबोल जीव प्यास से तड़पते हुए इधर-उधर भटकते नजर आते हैं। तपती धूप, सूखते जलस्रोत और कंक्रीट के फैलते जंगलों ने उनके लिए जीवन को और कठिन बना दिया है। ऐसे समय में यदि कोई उनके लिए पानी और दाने का छोटा सा इंतजाम कर दे, तो यह उनके लिए जीवनदान से कम नहीं होता। यही सोच आज कई शहरों में एक संवेदनशील अभियान का रूप ले चुकी है, जहां महिलाएं और समाज के जागरूक लोग मिलकर प्यासे परिंदों के लिए राहत बन रहे हैं। आठ साल पहले शुरू हुआ एक छोटा सा प्रयास आज जनआंदोलन का रूप ले चुका है। शुरुआत एक साधारण सी भावना से हुई थी, लेकिन इस भावना में इतनी सच्चाई और करुणा थी कि यह धीरे-धीरे सैकड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ती चली गई। एक दिन कुछ महिलाओं ने देखा कि भीषण गर्मी में गौरैया, कबूतर और गिलहरियां पानी की तलाश में भटक रही हैं। वे कभी किसी सूखी नलकी के पास बैठतीं, कभी किसी गड्ढे में जमे गंदे पानी की ओर जातीं, लेकिन उनकी प्यास पूरी नहीं हो पाती। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि उसने उनके दिल को झकझोर दिया। उसी क्षण उन्होंने तय कर लिया कि वे इन अबोल जीवों के लिए कुछ करेंगी। यही संकल्प आगे चलकर एक संगठित अभियान में बदल गया। शुरुआत में कुछ ही महिलाओं ने अपने घरों की छतों और आस-पास के पेड़ों पर मिट्टी के छोटे-छोटे बर्तन रखकर पानी भरना शुरू किया। धीरे-धीरे उन्होंने पार्कों, मंदिरों, गौशालाओं और सार्वजनिक स्थानों पर भी ऐसे बर्तन लगाने शुरू किए। हर दिन इन बर्तनों में पानी भरना, उन्हें साफ रखना और आसपास दाना डालना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। यह काम किसी दिखावे या प्रचार के लिए नहीं, बल्कि सच्ची सेवा भावना से किया जा रहा था। समय के साथ इस प्रयास ने लोगों का ध्यान खींचा। आसपास के लोग इस पहल से प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने घरों के बाहर पानी के बर्तन रखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह छोटा सा प्रयास एक बड़े अभियान में बदल गया, जिसमें आज कई महिलाएं और परिवार जुड़े हुए हैं। हजारों की संख्या में 'परिंदे' यानी पानी के बर्तन अलग-अलग स्थानों पर लगाए जा चुके हैं। यह अभियान सिर्फ पक्षियों को पानी देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह लोगों के भीतर छिपी संवेदनशीलता और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी को भी जागृत करने लगा है।

इस पहल की सबसे खास बात यह है कि इसमें जुड़ी महिलाएं इसे सिर्फ एक सेवा नहीं मानतीं, बल्कि इसे अपना कर्तव्य समझती हैं। उनका मानना है कि पक्षी हमारे पर्यावरण का एक अहम हिस्सा हैं। वे न केवल प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ये पक्षी नहीं रहेंगे, तो इसका असर पूरे पर्यावरण पर पड़ेगा। इसलिए उनकी रक्षा करना और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। आज जब शहरों में हरियाली कम होती जा रही है और प्राकृतिक जलस्रोत सूखते जा रहे हैं, तब पक्षियों के लिए पानी ढूंढना एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में यह अभियान उनके लिए जीवन की एक किरण बनकर सामने आया है। जिन इलाकों में पहले पक्षियों की चहचहाहट सुनाई नहीं देती थी, वहां अब फिर से उनकी आवाज गूंजने लगी है। यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि छोटे-छोटे प्रयास भी बड़ा असर डाल सकते हैं।

इस अभियान के पीछे एक गहरी सोच और समझ भी है। पानी के लिए मिट्टी या सिरेमिक के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये धूप में जल्दी गर्म नहीं होते और पानी को ठंडा बनाए रखते हैं। बर्तनों को हमेशा छांव में रखा जाता है, ताकि पानी ज्यादा देर तक उपयोगी रहे। हर दिन पानी बदलने और बर्तन साफ रखने का विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि पक्षियों को स्वच्छ पानी मिल सके। साथ ही, पानी के पास थोड़ा दाना भी रखा जाता है, जिससे उन्हें भोजन की भी सुविधा मिल सके। यह पहल हमें यह सिखाती है कि इंसानियत केवल इंसानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सच्ची मानवता वही है, जो हर जीव के प्रति करुणा और दया का भाव रखे। जब हम किसी प्यासे पक्षी के लिए पानी रखते हैं, तो यह केवल एक छोटा सा काम नहीं होता, बल्कि यह प्रकृति के प्रति हमारे प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक होता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं, बल्कि लाखों-करोड़ों जीवों के साथ इसे साझा करते हैं। आज के समय में, जब जीवन की भागदौड़ में लोग अपने आसपास की दुनिया को नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसे अभियान हमें रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। वे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि थोड़ी सी संवेदनशीलता और प्रयास से हम किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़े स्तर पर कुछ करें; एक छोटा सा कदम भी किसी के लिए बहुत मायने रख सकता है। भीषण गर्मी के इन दिनों में, जब सूरज की तपिश हर चीज को झुलसा रही होती है, तब एक कटोरा पानी किसी प्यासे पक्षी के लिए अमृत के समान होता है। यह सिर्फ उसकी प्यास नहीं बुझाता, बल्कि उसे जीवन जीने की ताकत भी देता है। और जब वह पक्षी पानी पीकर चहचहाते हुए उड़ जाता है, तो वह दृश्य किसी भी इंसान के दिल को सुकून और खुशी से भर देता है।

पारिवारिक कलह से रिश्तों का रोज़ होता पतन

भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, लेकिन देश में बढ़ते अपराध—विशेषकर घरेलू और पारिवारिक हिंसा के जघन्य मामलों—में निरंतर वृद्धि होना एक सभ्य समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। आज के आधुनिक दौर में जब भी हम समाचार पत्रों या न्यूज़ चैनलों से रूबरू होते हैं, तो राजनीति से इतर आपराधिक घटनाओं और पारिवारिक कलह से जुड़ी खबरों का प्रतिशत लगातार बढ़ता दिखाई देता है। मीडिया द्वारा इन घटनाओं को प्रमुखता से दिखाना अब मजबूरी बन गई है, क्योंकि देश के लगभग हर धर्म, वर्ग और समाज में पारिवारिक हिंसा का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जो कई बार जघन्य अपराधों का रूप ले लेता है। भारत विश्व को शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देने वाला देश माना जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि हमारे अपने ही परिवारों में रिश्तों के बीच दूरियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं कि साथ बैठकर भोजन करना भी कठिन होता जा रहा है। सिर्फ भाई-भाई के रिश्ते ही नहीं, बल्कि पति-पत्नी के संबंधों में भी जिस गति से अलगाव बढ़ रहा है और उसके भयावह परिणाम सामने आ रहे हैं, वह पूरे समाज के लिए गहन चिंतन का विषय है। यह स्थिति हर धर्म, हर वर्ग और हर व्यक्ति को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है।

आधुनिकता की दौड़ में हमने नई पीढ़ी को महंगी शिक्षा और भौतिक सुख-सुविधाएँ तो भरपूर दी हैं, लेकिन उन्हें सहनशीलता, धैर्य, अपनत्व, विनम्रता और परिवार को साथ लेकर चलने के संस्कार देने में हम कहीं पीछे रह गए हैं। परिणामस्वरूप, नवपीढ़ी में धैर्य और सहनशीलता का अभाव बढ़ रहा है, जो पारिवारिक कलह को जन्म देकर कई बार गंभीर अपराधों में बदल जाता है। आज कोई भी समाज या व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह पारिवारिक कलह से पूरी तरह मुक्त है। जो घटनाएँ आज हम समाचारों में देख-सुन रहे हैं, वे कल किसी भी परिवार की वास्तविकता बन सकती हैं। कहीं पैसों के विवाद, कहीं अवैध संबंधों की आशंका, कहीं कर्ज का दबाव, तो कहीं नशे की लत या पारिवारिक हस्तक्षेप—इन सभी कारणों से महानगरों से लेकर गाँवों तक रिश्तों का पतन तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि कई बार कम उम्र और कम समझ वाले लोग भी संदेह या आवेग में आकर अपने ही जीवनसाथी की हत्या जैसे जघन्य अपराध कर बैठते हैं। वहीं, कर्ज और पारिवारिक तनाव से परेशान होकर अपने ही मासूम बच्चों की हत्या कर आत्महत्या करने की घटनाएँ भी समाज को झकझोर देती हैं।

यह भी एक कटु सत्य है कि पारिवारिक कलह अब केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक सीमित नहीं रही। जहाँ गरीब परिवारों में इसे आर्थिक तंगी का परिणाम माना जाता है, वहीं संपन्न और भौतिक रूप से समृद्ध घरों से उठती कलह की आवाजें रिश्तों के आंतरिक विघटन की ओर संकेत करती हैं। हर दिन अवैध संबंधों की शंका और अविश्वास के चलते प्रेम, विश्वास और अपनत्व जैसे रिश्तों का गला घोंटने की घटनाएँ सामने आ रही हैं। ऐसे में समाज के हर वर्ग को पारिवारिक मूल्यों के संरक्षण और रिश्तों की गरिमा बनाए रखने के लिए गंभीरता से विचार करना होगा। यदि हम परिवार की खुशहाली, सौहार्द और विश्वास को बनाए रखना चाहते हैं, तो मजबूत और संतुलित दाम्पत्य जीवन पर सामूहिक मंथन समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है।

अरविंद रावल

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत उद्यमियो को 10 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाए,, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

सीतापुर 7 जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमियो को अधिकतम रूपया 10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंको के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। इसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थी हेतु पूंजीगत (सावधि) ऋण पर बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज् में से 4 प्रतिशत ब्याज् उद्यमी द्वारा वहन किया जाएगा, शेष ब्याज का भुगतान ब्याज् उपादान के रूप में 05 वर्षो तक प्रति वर्ष 20 प्रतिशत घटते क्रम में शेष पूँजीगत ऋण पर वित्त पोषण करने वाली बैंक को उपलब्ध कराया जायेगा। आरक्षित वर्ग, (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, एवं महिलाओं) को पूंजीगत (सावधि) ऋण पर बैंक द्वारा प्रभारित समस्त ब्याज् की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में 20 प्रतिशत घटते पूँजीगत ऋण पर 05 वर्षो तक उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। आई0 टी0 आई0 तकनीकी योग्यता/परंपरागत कारीगरों/सेवायोजन में पंजीकृत उद्यमियों को वरीयता प्रदान की जायेगी तथा योजनान्तर्गत ऑनलाइन स्क्रूटनी के माध्यम से पात्र उद्यमियों का चयन किया जायेगा। इच्छुक लाभार्थी विभागीय वेबसाइट https://mmgrykhadi.upsdc.gov.in/ पर अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते है तथा अन्य विस्तृत जानकारी हेतु लाभार्थी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय विकास भवन लालबाग कं0नं0-126,127 में सम्पर्क स्थापित कर सकते है।

मनरेगा कर्मियों की कलमबंद हड़ताल, बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

मिश्रिख (सीतापुर) ग्राम रोजगार सेवक वेलफेयर एसोसिएशन ब्लॉक मिश्रिख के बैनर तले मनरेगा से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को कलमबंद हड़ताल का ऐलान किया। इस दौरान कर्मचारियों ने खंड विकास अधिकारी मिश्रिख को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की। हड़ताल के आह्वान के तहत ग्राम रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, तकनीकी सहायक और लेखा सहायकों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं, जिन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में मजबूर होकर उन्हें कलमबंद हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष अमित कश्यप, अश्वनी शुक्ल, सना खान, शिवसागर, रामनाथ सहित करीब आधा सैकड़ा मनरेगा कर्मी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

CM योगी के निर्णय से यूपी के किसानों को राहत, अब बिना फार्मर रजिस्ट्री के भी कर सकेंगे गेहूं की खरीद-बिक्री

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फार्मर रजिस्ट्री न करा पाने वाले किसानों को गेहूं खरीद प्रक्रिया में बड़ी राहत दी है। उन्होंने सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद के लिए फार्मर रजिस्ट्री की बाध्यता समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों को तत्काल प्रभाव से व्यवस्था लागू करने के लिए कहा गया है। अब वे किसान भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं बेच सकेंगे, जो अब तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करा पाए है। इससे खरीद प्रक्रिया में तेजी आने और अधिक किसानों को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में हर किसान की फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जानी है। इसके लिए 15 मई आखिरी तिथि है और 23 मई के बाद इस प्रक्रिया के तहत पंजीकरण न कराने वाले किसानों को किसी भी सरकारी योजना, अनुदान आदि का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले प्रदेश में चल रही गेहूं की सरकारी खरीद में उपज विक्रय के लिए किसान की फार्मर रजिस्ट्री होना अनिवार्य कर दिया गया था। प्रदेश में 2,88,70,495 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जानी है और सोमवार शाम तक 2,13,96,428 किसानों का ही पंजीकरण हो पाया है। क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की रफ्तार सुस्त होने के पीछे फार्मर रजिस्ट्री की बाध्यता को भी कारण माना जा रहा था।

फार्मर रजिस्ट्री की बाध्यता खत्म करने के निर्देश

किसानों की समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री ने सोमवार को खरीद प्रक्रिया में फार्मर रजिस्ट्री की बाध्यता को शिथिल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रय केंद्रों पर गेहूं बिक्री के लिए आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बेतहाशा गर्मी को देखते हुए सभी क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए पानी, पंखा, छाया आदि व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार सोमवार शाम तक 41,964 किसानों से 2,36,479 टन गेहूं की खरीद हुई है। फार्मर रजिस्ट्री की बाध्यता खत्म होने के बाद क्रय केंद्रों पर किसानों की आमद बढ़ने की संभावना है।

महमूदाबाद ब्लॉक परिसर में भाकियू (टिकैत) का जोरदार प्रदर्शन

● प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद- सीतापुर विकास खण्ड महमूदाबाद के परिसर में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की तहसील इकाई के पदाधिकारियों और किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व में दिए गए ज्ञापन के आधार पर यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। किसानों ने गौशालाओं में चारा-भूसे की समुचित व्यवस्था, ग्राम पंचायतों में खराब पड़े सरकारी हैंडपंपों की मरम्मत सहित अन्य समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। भाकियू पदाधिकारियों का कहना था कि 19 तारीख तक समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके विरोध में 20 तारीख को धरना-प्रदर्शन की चेतावनी के तहत सोमवार सुबह 11 बजे से प्रदर्शन शुरू किया गया।

प्रदर्शन के दौरान तहसील अध्यक्ष सम्मत कुमार वर्मा ने प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने सचिव अर्जुन गुप्ता पर काम में लापरवाही और हीला हवाली का आरोप लगाया, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। इस दौरान किसान यूनियन के कई तहसीलों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें महमूदाबाद ब्लॉक अध्यक्ष पवन कुमार वर्मा, तहसील बिसवां के तहसील अध्यक्ष शिवराज सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। साथ ही बड़ी संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में मौजूद रहे। तहसील अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हुआ, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी ब्लॉक प्रशासन की होगी।

बेहतर प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र का हुआ सम्मान

सीबीएससी बोर्ड परीक्षा में हासिल किया 95 प्रतिशत अंक

लखनऊ। औरंगाबाद जागीर के बिजनौर रोड हिमालयन कॉलोनी स्थित लेन संख्या-तीन में रहने वाले मेधावी छात्र द्वारा सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 95 प्रतिशत अंक अर्जित कर विद्यालय, कॉलोनी और परिवार का मान बढ़ाने वाले छात्र तनय श्रीवास्तव को कॉलोनी वासियों व स्थानीय लोगों ने एक कार्यक्रम में माल्यार्पण कर प्रोत्साहित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सिंचाई विभाग में इंजीनियर के पद पर कार्यरत तनय के पिता संदीप श्रीवास्तव व सिंचाई विभाग में ही प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात मां निवेदिता श्रीवास्तव भी मौजूद रही। होनहार छात्र तनय ने बताया कि उनका बड़ा भाई तनिष श्रीवास्तव वाराणसी स्थित बीएचयू विश्वविद्यालय से आईआईटी की पढ़ाई कर रहा है। उनकी इस सफलता का श्रेय उनके माता, पिता, शिक्षकों और उनके बड़े भाई व नियमित परिश्रम को जाता है। तनय ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि भविष्य में एक अच्छा इंजीनियर अथवा प्रशासनिक अधिकारी बन कर वह देश की सेवा करना चाहते है।

स्वर्ण जयंती समारोह में 'अमर्यादित' आचरण का वीडियो वायरल, सवालों के घेरे में कॉलेज प्रशासन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद-सीतापुर जनपद के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक, महमूदाबाद के स्वर्ण जयंती समारोह की गरिमा पर उस समय प्रश्नचिह्न लग गया, जब कार्यक्रम से जुड़ा एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। यह आयोजन संस्थान के गौरवशाली 50 वर्षों की उपलब्धि को चिह्नित करने के लिए किया गया था, जिसका शुभारंभ पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉ. अम्मार रिजवी और क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य के सानिध्य में हुआ था।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ युवक कार्यक्रम स्थल पर कथित तौर पर प्रतिबंधित बोतलों (मदिरा) के साथ दिखाई दे रहे हैं। एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के परिसर में और इतने बड़े स्तर के सार्वजनिक समारोह में इस तरह के 'अमर्यादित' व्यवहार ने स्थानीय लोगों और शिक्षाविदों को स्तब्ध कर दिया है। वीडियो सामने आने के बाद से ही लोग कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक वातावरण की शुचिता पर तीखे सवाल उठा रहे हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। संस्थान के प्रधानाचार्य ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात वह अध्यक्ष महोदय के साथ भोजन के लिए चले गए थे। इसी बीच कुछ पूर्व छात्र (एलुम्नाई) परिसर में प्रवेश कर गए थे। जैसे ही इस अवांछनीय गतिविधि की सूचना मिली, तत्काल उन्हें वहां से बाहर कर दिया गया।

कालेज प्रशासन के स्पष्टीकरण के बावजूद क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इतने महत्वपूर्ण आयोजन में बाहरी या पूर्व छात्रों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध नहीं थे? एक गरिमामयी समारोह में इस प्रकार के आचरण से संस्थान की छवि को जो क्षति पहुंची है, उसका उत्तरदायी कौन है? फिलहाल, सोशल मीडिया पर लोग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और कॉलेज प्रशासन से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु ठोस कदम उठाने की अपेक्षा कर रहे हैं।

रहीमाबाद में आमने-सामने बाइक टक्कर, युवक गंभीर रूप से घायल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे बाइक सवार को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मलिहाबाद थाना क्षेत्र के बलदेव खेड़ा गांव निवासी मुकेश पाल अपने भाई दीपक के साथ बाइक से सब्जी लेकर घर वापस लौट रहे थे। जैसे ही वे रहीमाबाद थाना क्षेत्र के लोहई गांव के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे जमुनिया गांव निवासी चंद्रपाल की बाइक से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े।

इस हादसे में मुकेश पाल को गंभीर चोटें आई और उनका पैर टूट गया। हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और घायल को संभालते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल मुकेश पाल को तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त बाइकों को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हुआ हो सकता है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की आवश्यकता को उजागर किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर तेज रफ्तार के कारण हादसे होते रहते हैं, जिस पर प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

जेपी सिंह बने कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष

लालगंज (रायबरेली)। कांग्रेस पार्टी ने संगठन विस्तार के तहत शिक्षक प्रकोष्ठ में नई जिम्मेदारी सौंपी है। बैसवारा इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य जयप्रकाश सिंह को शिक्षक प्रकोष्ठ का जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उनके मनोनयन की खबर मिलते ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कांग्रेसी नेताओं और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी। अपने मनोनयन पर जेपी सिंह ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार राय और जिला अध्यक्ष केसी शुक्ला का धन्यवाद किया। जेपी सिंह ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह, महेश प्रसाद शर्मा, रणवीर सिसोदिया, संजय तिवारी, जयहिंद सिंह, अरविंद अग्निहोत्री, दीपक सिंह, संतोष तिवारी, दीपक त्रिवेदी, भैया जी और सनी सिंह सहित कई लोगों ने हर्ष जताया।

सुरक्षित, प्रभावी एवं कम जोखिम वाले उपचार विकल्प उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी रेडियोलॉजी: विशेषज्ञ

● लखनऊ में आयोजित हुआ इंडियन सोसाइटी ऑफ वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, यूपी स्टेट कॉन्फ्रेंस 2026

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। इंडियन सोसाइटी ऑफ वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी (ISVIR), उत्तर प्रदेश चैप्टर द्वारा आयोजित दो दिवसीय स्टेट कॉन्फ्रेंस 2026 की शुरुआत होटल सेंट्रम, लखनऊ में शनिवार को हुई। यह दो दिवसीय अकादमिक सम्मेलन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी (IR) के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और तकनीकों पर केंद्रित रहेगा, जिसमें देश-विदेश के विशेषज्ञ भाग लें रहे हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जिसे हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन (हस्ष्ट) द्वारा सुपर-स्पेशियलिटी के रूप में मान्यता दी गई है, आधुनिक चिकित्सा में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह तकनीक बिना बड़े ऑपरेशन के, केवल छोटी सुई या कैथेटर के माध्यम से जटिल बीमारियों का इलाज संभव बनाती है। विशेषज्ञों के अनुसार इंडियन सोसाइटी ऑफ वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी न केवल ओपन सर्जरी के जोखिम को कम करता है, बल्कि कई मामलों में अंग विच्छेदन तक को टाल सकता है। उदाहरण के तौर पर: डायबिटिक मरीजों में पैर की ब्लॉकेज को एंजियोप्लास्टी द्वारा खोलकर पैर काटने की नौबत से बचाया जा सकता है। कैंसर के मरीजों में ट्यूमर एब्लेशन या कीमोएंबोलाइजेशन के जरिए बिना बड़ी सर्जरी के ट्यूमर का इलाज किया जा सकता है।

इस सम्मेलन में प्रदेश के प्रमुख संस्थानों- किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, एसजीपीजीआई लखनऊ, डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ तथा मेदांता लखनऊ – की सक्रिय भागीदारी है, जो राज्य में चिकित्सा शिक्षा और क्लिनिकल सहयोग को और मजबूत बनाएगी। विशिष्ट अतिथियों में प्रो. एम.एल.बी. भट्ट (निदेशक, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान) तथा मेजर जनरल प्रो. अमित देवगन (कुलपति, एबीवी मेडिकल यूनिवर्सिटी) शामिल रहे, जो इस कार्यक्रम की शैक्षणिक महत्ता को रेखांकित करते हैं। इस आयोजन में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ भी अपने अनुभव साझा करेंगे। विशेष रूप से डॉ. शम्स इकबाल बौस्तान तथा डॉ. सलील कर्खानिस (बर्मिंघम, इंग्लैंड) द्वारा लाइव फैकल्टी लेक्चर आयोजित किए जाएंगे, जो प्रतिभागियों को वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के आयोजन में प्रो. अनित परिहार, विभागाध्यक्ष (रेडियोडायग्नोसिस), केजीएमयू की सक्रिय भागीदारी है और वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दो दिवसीय वैज्ञानिक कार्यक्रम में न्यूरोइंटरवेंशन, हेपेटोबिलियरी इंटरवेंशन, वैस्कुलर प्रक्रियाएं, ऑन्कोलॉजिक थेरेपी तथा मस्कुलोस्केलेटल इंटरवेंशन जैसे विषयों पर कीनोट लेक्चर, पैनल डिस्कशन और हैंड्स-ऑन वर्कशॉप्स आयोजित होंगी। विशेष कार्यशालाओं में ट्यूमर एब्लेशन और तीव्र स्ट्रोक प्रबंधन जैसे उन्नत प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सम्मेलन में पीजी रेजिडेंट्स के लिए पेपर प्रेजेंटेशन और क्विज प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, जिससे युवा रेडियोलॉजिस्ट्स में शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। देशभर से विशेषज्ञों और चिकित्सकों की भागीदारी के साथ, इंडियन सोसाइटी ऑफ वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी यूपी स्टेट कॉन्फ्रेंस 2026 इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के विकास को नई दिशा देने और मरीजों को सुरक्षित, प्रभावी एवं कम जोखिम वाले उपचार विकल्प उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

जल जीवन मिशन में रायबरेली की सराहना

● डीएम पेयजल 'संवाद' में सम्मानित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली:- भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित 'जल जीवन मिशन' के तहत रायबरेली जनपद ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 15 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 'पेयजल संवाद' के 7 वें संस्करण में रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रभावी कार्यान्वयन, नवाचार और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से 'हर घर जल' के लक्ष्य को गति देने के लिए प्रदान किया गया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस उच्च स्तरीय संवाद की अध्यक्षता जल जीवन मिशन के सचिव श्री अशोक के. के. मीणा ने की। इस दौरान राष्ट्रीय मिशन निदेशक कमल किशोर सोन ने जिलाधिकारी द्वारा दी गई प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि रायबरेली में अपनाई गई रणनीतियां और डेटा-संचालित सूचना तंत्र अन्य जिलों के लिए प्रेरणादायी है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले ने न केवल तकनीकी रूप से बल्कि जन-भागीदारी के मामले में भी नए मानक स्थापित किए हैं।

संवाद के दौरान जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने जिले में जेजेएम (JJM) 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के दूसरे चरण को लेकर किए जा रहे प्रयासों का विवरण साझा किया। उन्होंने बताया कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करना और गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. राजशेखर, राज्य मिशन निदेशक प्रभास कुमार, मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) विशाल कुमार यादव और अधिशाषी अभियंता एस. रहमान सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उच्च शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी नहीं स्थापित हो सकी भगवान परशुराम की मूर्ती-जीतेन्द्र प्रसाद द्विवेदी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हरदोई (उत्तर प्रदेश)- प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व हिन्दू साम्राज्य एवं वरिष्ठ समाजसेवी शाहजहांपुर जितेन्द्र प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में कुछ ब्राह्मण समाज के युवा भगवान श्री परशुराम जी की प्रतिमा 19 अप्रैल अक्षय तृतीया को को ग्राम रामपुर थाना बघौली जिला हरदोई में स्थापित करना चाहते थे भगवान परशुराम जी की पांच फिट की भव्य प्रतिमा कुशल कारीगरों के द्वारा शाहजहांपुर में तैयार हुई ये प्रतिमा हुई मूर्ती स्थापना भण्डारा एवं भोभा यात्रा के लिए बघौली थाना प्रभारी से मुलाक़ात की गरी एस एच ओ बघौली ब्रजेश कुमार मिश्रा ने कहा इस कार्यक्रम के लिए उपजिलाधिकारी से परमीशन दे लीजिए दिनांक 6/4/26 को अशोक कुमार मिश्रा जिनकी निजी भूमि पर मूर्ती की स्थापना होनी थी उनके द्वारा भूमि के खतौनी एवं ग्राम प्रधान के शपथ पत्र संलग्न करके आवेदन दिया गया जब मूर्ती तैयार करवाकर दिनांक 17/4/26 को चिन्हित भूमि पर पहुंची उसी समय थाना बघौली से पुलिस पहुंची मूर्ती को स्थापित करने से ये कहकर मना कर दिया कि तुम्हारी परमीशन कैंसिल हो गयी दिनांक 18/4/26 को मूर्ती स्थापना के लिए पूरे दिन प्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे किसी ने नहीं सुना 18 शाम को एस एच ओ बघौली फोर्स सहित मूर्ती उठाकर थाने ले जाने के लिए आ गये ग्रामीणो के समझाने से मूर्ती को वहां से उठवा कर अशोक कुमार मिश्रा के घर पर रखवा कर वहीं पुलिस बल के साथ डेरा डाल दिया मूर्ती स्थापित करने को लेकर ग्रामीणों एवं पुलिस प्रशासन के बीच कई राउंड बार्ता हुई लेकिन हर वार विफल रही मूर्ती स्थापना को लेकर ग्रामीण एवं ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी के आवास पर उनसे मिले मंत्री जी ने एस डी एम से फोन से बात करके ग्रामीणों से कहा जाओ मूर्ती स्थापित करो जाकर जब ग्रामीण गांव पहुंचकर मूर्ती स्थापना के लिए चले तभी पुलिस ने रोक दिया एस एस एच ओ ने कहा एस डी एम से बात करवा दीजिए ग्रामीणों ने बहुत कोशिश के बाद एस डी एम और मंत्री जी ने फोन रिसीव नहीं किया शाहजहांपुर से पहुंचे समाज सेवी जितेन्द्र प्रसाद द्विवेदी ने एस एच ओ बघौली से बात की तो एस एच ओ ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही मूर्ती स्थापना की परमीशन प्रशासन द्वारा करवा कर मूर्ती स्थापित एवं शोभायात्रा मैं करवाऊंगा समाजसेवी जितेन्द्र प्रसाद द्विवेदी के समझाने पर ग्रामीण मान गये एवं ज़िद छोड़कर भगवान श्री परशुराम जी की पूजा कर भण्डारा का शुभारम्भ किया गया ये समझ में नहीं आता कि प्रशासन पर किसका दबाव था कि अपनी निजी भूमि जिस पर पहले से देव स्थान है उस पर मूर्ती स्थापित नहीं होने दी गयी जब कि केंद्र एवं राज्य में सनातनी सरकार है सनातनी सरकार में सनातन धर्म अब मज़ाक बनकर रह गया है।

किशोरी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद-सीतापुर। पुलिस ने महमूदाबाद क्षेत्र में हुई एक किशोरी की आत्महत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवक पर किशोरी को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। बीते 18 अप्रैल को थाना महमूदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक 15 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। घटना के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, जिसकी रिपोर्ट में मृत्यु का कारण 'एंटी-मॉर्टम हैंगिंग' (मृत्यु से पहले फांसी लगाना) पाया गया। मृतका के चाचा, अहिमान सिद्दकी की तहरीर पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए, पुलिस की गहन पड़ताल और तकनीकी साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि मृतका की बातचीत सदरपुर क्षेत्र के नबीगंज निवासी साहिबे आलम और ईबरान उर्फ इमरान से होती थी। घटना से कुछ समय पहले इनके बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक और विवाद हुआ था, जिससे क्षुब्ध होकर बालिका ने यह आत्मघाती कदम उठाया। पूछताछ में यह तथ्य भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी साहिबे आलम पहले मृतका के चाचा के मुर्गी फार्म पर काम करता था। इस वजह से दोनों पक्ष एक-दूसरे को पहले से जानते थे। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) दुर्गेश सिंह और क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद वेदप्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई की। उपनिरीक्षक विनोद कुमार गिरि और हेड कांस्टेबल वेगवान सिंह की टीम ने मुख्य अभियुक्त साहिबे आलम पुत्र मुकीद को गिरफ्तार किया। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अकबरपुर में जल्द बनेगा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन: विवेक मौर्य

● परिवहन मंत्री से माँग में मिला भरोसा, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया: विवेक मौर्य

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अकबरपुर/ अंबेडकरनगर। विख्यात समाजसेवी संस्था नारायण फाउंडेशन के संरक्षक भाजपा नेता विवेक मौर्य ने दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश से भेंट कर उनसे अकबरपुर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की माँग की। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विवेक मौर्य की माँग पर आश्वासन देते हुए कहा कि वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ोत्तरी को देखते हुए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है और अकबरपुर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए प्रक्रिया शीघ्र शुरू कराई जाएगी। विवेक मौर्य ने अकबरपुर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए परिवहन मंत्री के सकारात्मक रूख पर उनका आभार प्रकट किया है।

परिवहन मंत्री से मुलाक़ात पर विवेक मौर्य ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपनी विभागीय कार्यपद्धति से उत्तर प्रदेश में परिवहन सेवाओं व आधारभूत ढांचे के विकास में अभूतपूर्व कार्य किया है। परिवहन मंत्री ने अकबरपुर में परिवहन सेवाओं के उन्नयन व नई सुविधाओं को देने में कभी कोई कमी नहीं रखी। आज मैंने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से भेंट कर उनसे अकबरपुर में लगभग ?5.50 करोड़ की लागत से बनने वाले इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की माँग की जिस पर उनका रुख़ काफ़ी सकारात्मक रहा और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।

अपनी इस भेंट वार्ता में मैंने उन्हें अकबरपुर में दशकों से लंबित व बहुप्रतीक्षित बस स्टेशन के स्थानांतरण व नए बस अड्डे के निर्माण के लिए लगातार मेरी माँग का मान रखने व इसके लिए 32 करोड़ रुपये मंजूर करने के लिए उनका अकबरपुर की समस्त सम्मानित जनता की ओर से हार्दिक आभार प्रकट किया। परिवहन मंत्री की ओर से यह भी आश्वासन मिला कि अकबरपुर में परिवहन सेवाओं के क्षेत्र में कभी कोई आभाव नहीं रहेगा।

उत्तर प्रदेश में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, यूपी में 24 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, अयोध्या, बाराबंकी और गाजीपुर समेत कई जिलों में नए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की नियुक्ति की गई है। अविनाश कुमार को अलीगढ़, शशांक त्रिपाठी को अयोध्या और इशान प्रताप सिंह को बाराबंकी का जिला अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा, शासन स्तर पर भी कई वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यूपी में आईएएस अधिकारियों के बड़े स्तर के ट्रांसफर का नया दौर चल रहा है। रविवार को 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले होने के बाद सोमवार को एक बार फिर 24 अधिकारियों को नई जगहों पर भेजा गया। आज कुल 10 जिलों के जिला मजिस्ट्रेट बदले गए हैं।

संक्षिप्त खबरें

कर्नाटकः ED ने कांग्रेस विधायक के बेटों समेत अन्य के ठिकानों पर मारा छापा, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कार्रवाई

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कर्नाटक में कई जगहों पर छापामारी की। इसमें कर्नाटक कांग्रेस विधायक एन.ए. हरिस के बेटों से जुड़े परिसर शामिल हैं। यह कार्रवाई क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई है। अधिकारियों ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत श्रीकृष्ण रमेश उर्फ श्रीकी और अन्य आरोपियों के खिलाफ करीब 12 परिसरों पर तलाशी ली जा रही है। ये छापा बेंगलुरु समेत कर्नाटक के विभिन्न स्थानों पर किए गए। छापों में विधायक एन.ए. हरिस के बेटों मोहम्मद हरिस नालापड़ और ओमार फारूक नालापड़ से जुड़े परिसर भी शामिल हैं।

क्रिप्टो हैकिंग और बिटकॉइन चोरी से जुड़ा मामला

जांच कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर और चार्जशीट पर आधारित है। इनमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वेबसाइटों को हैक करना, बिटकॉइन चोरी, एक्सटॉर्शन और एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन जैसे अपराध शामिल हैं। ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपियों का तरीका यह था कि वे वेबसाइटों और क्रिप्टो वॉलेट्स को हैक करके वर्चुअल डिजिटल एसेट्स चुराते थे। फिर इन्हें क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए बेचा जाता था। प्राप्त आय को बैंक खातों के माध्यम से लेयरिंग करके व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता था।

विधायक के बेटे मुख्य लाभार्थी?

ईडी के अनुसार, मोहम्मद हरिस नालापड़ और ओमार फारूक नालापड़ श्रीकृष्ण रमेश उर्फ श्रीकी के करीबी सहयोगी हैं और वे अपराध से प्राप्त आय के मुख्य लाभार्थी बताए जा रहे हैं। एन.ए. हरिस शांतिनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं। छापों की इस कार्रवाई से कर्नाटक की राजनीति में हलचल मच गई है। श्रीकी पर 2017 से ही वेबसाइट हैकिंग और बिटकॉइन चोरी के आरोप हैं। ईडी अब मनी ट्रेल और लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है।

अब सरकारी गवाह बनना चाहती हैं Jacqueline Fernandez, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED से मांगा जवाब

पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। यह मामला 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर मुख्य आरोपी हैं

नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अभिनेत्री Jacqueline Fernandez की उस अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को अतिरिक्त समय दे दिया है, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति देने की मांग की है।

आठ मई को ईडी देगी अपना जवाब

विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई आठ मई के लिए निर्धारित की है। इसी दिन ईडी को अब अपना जवाब देना होगा। अदालत ने इससे पहले 17 अप्रैल को जैकलीन की ओर से दायर आवेदन पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सोमवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने समय की मांग की थी। बता दें कि जांच के दौरान कई बार समन मिलने के बाद ईडी ने पहली बार जैकलीन फर्नांडिस को पूरक आरोपपत्र में आरोपित बनाया था।

महाठग सुकेश है मुख्य आरोपी

इस मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर मुख्य आरोपित है, जिस पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से करीब 200 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मकोका के तहत मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना पालोज ने हवाला मार्ग और शेल कंपनियों के जरिए अवैध धन को इधर-उधर किया। इस मामले में देशभर में अन्य जांच भी जारी हैं।

नेपाल के पीएम बालेन शाह का बड़ा एक्शन, विश्वविद्यालय परिसर से राजनीतिक संघ को हटाने का दिया फरमान

● प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालयों को आगे निर्देश दिया कि वे शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करें और परीक्षा परिणाम एक महीने के भीतर प्रकाशित करें। इसी तरह, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा कि मंत्रालय ने राजनीतिक दलों से जुड़े ढांचों को समाप्त करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं, और मौजूदा कानून इनके कार्यान्वयन में कोई बाधा नहीं डालते हैं।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि वे पार्टी से जुड़े संघों को तुरंत हटा दें। प्रधानमंत्री ने सोमवार को अपने कार्यालय में कुलपतियों के साथ हुई एक बैठक के दौरान यह निर्देश दिया, और उन्हें आदेश दिया कि वे परिसरों से पार्टी से जुड़े छात्र और कर्मचारी संघों को हटाने के फैसले को तुरंत लागू करें। तीन घंटे तक चली इस लंबी बैठक में, प्रधानमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनके कार्यालय के अनुसार, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से पार्टी से जुड़ी संरचनाओं को हटाने में कोई भी कानून बाधा नहीं बनेगा।

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि अस्पताल, परिसर और स्कूल 'पवित्र स्थान' हैं, शाह ने कहा कि ऐसी जगहों पर किसी भी राजनीतिक दल के झंडे, प्रभाव या संगठनात्मक ढांचे की अनुमति नहीं होगी। शाह ने यह भी सुझाव दिया कि जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, उन्हें अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों से हट जाना चाहिए और पूरी तरह से राजनीति में शामिल होना चाहिए। चर्चा के दौरान, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. धनेश्वर नेपाल ने कहा कि छात्र संगठनों को खत्म करने के प्रयासों के कारण धमकियाँ और हमले हुए हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री शाह ने कुलपतियों को निर्देश दिया कि यदि राजनीतिक ढांचों को हटाने के दौरान कोई सुरक्षा संबंधी समस्या आती है, तो वे तुरंत संबंधित मंत्रालय या प्रधानमंत्री सचिवालय को सूचित करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार सुरक्षा समन्वय सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, और कहा कि पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। शाह ने कुलपतियों से यह भी आग्रह किया कि वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें।

प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालयों को आगे निर्देश दिया कि वे शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करें और परीक्षा परिणाम एक महीने के भीतर प्रकाशित करें।

इसी तरह, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा कि मंत्रालय ने राजनीतिक दलों से जुड़े ढांचों को समाप्त करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं, और मौजूदा कानून इनके कार्यान्वयन में कोई बाधा नहीं डालते हैं। बैठक के दौरान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. दीपक आर्यल ने कहा कि 'तद्दठु-' आंदोलन और हालिया चुनावों के बाद छात्र और कर्मचारी संगठन धीरे-धीरे निष्क्रिय हो गए हैं। मिड-वेस्ट यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. डॉ. ध्रुव कुमार गौतम, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. डॉ. बीजू कुमार थापलिया और सुदूरपश्चिम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. डॉ. हेमराज पंत ने कहा कि कुछ घटक परिसरों में राजनीतिक तनाव अभी भी बना हुआ है। हालांकि, अन्य विश्वविद्यालयों और अकादमियों के कुलपतियों ने कहा कि उनके संस्थानों में राजनीतिक गतिविधियां बहुत कम हैं, और उन्होंने विश्वास जताया कि अधिक सख्त प्रशासन शैक्षणिक क्षेत्र में राजनीतिक प्रभाव को खत्म करने में मदद कर सकता है।

न्यूजीलैंड-कनाडा मैच में हुई थी फिक्सिंग, कप्तान पर लगा आरोप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) क्रिकेट कनाडा के विरुद्ध अपने भ्रष्टाचार रोधी संहिता के कथित उल्लंघन की जांच कर रहा है। इसमें टी-20 विश्व कप में 17 फरवरी को चेन्नई में खेला गया मैच भी शामिल है, जिसमें कनाडा की टीम को हार का सामना करना पड़ा था। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। चेपॉक स्टेडियम में खेले गए उस मैच में कनाडा आठ विकेट से हार गया था। हाल ही में प्रसारित 43 मिनट की डाक्यूमेंट्री 'करप्शन, क्राइम एंड क्रिकेट' में भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर किए जाने के बाद आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी इकाई (AC) इसकी गहन जांच कर रही है। कनाडा ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 173 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने लक्ष्य केवल 15.1 ओवर में हासिल कर लिया। ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार आरोपों पर एसीयू दो सक्रिय जांच कर रही है, जिनमें खासकर कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा द्वारा किए गए पांचवें ओवर की जांच शामिल है।

दिलप्रीत बाजवा संदेह के घेरे में

ऑलराउंडर बाजवा को टूर्नामेंट से तीन सप्ताह पहले ही कप्तान नियुक्त किया गया था। उन्होंने न्यूजीलैंड के विरुद्ध ओवर की शुरुआत नो-बॉल से की, उसके बाद लेग साइड में वाइड गेंद फेंकी और कुल 15 रन लुटाए। आईसीसी की इंटीग्रिटी यूनिट के अंतरिम महाप्रबंधक एंड्रयू एफग्रेव ने फिलहाल किसी भी आरोप पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी जांच कनाडा पूर्व कोच खुर्रम चौहान से जुड़ी एक लीक हुई फोन रिकार्डिंग से संबंधित है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बोर्ड के कुछ सीनियर सदस्यों ने उन पर कुछ खिलाड़ियों को चुनने के लिए दबाव डाला था। रिकार्डिंग में मैचों में फिक्सिंग के प्रयासों के दावे भी शामिल हैं।

'सपा के 'पीडीए' का खेल समझ चुकी है जनता', केशव मौर्य ने विपक्ष पर नारी शक्ति को कमजोर करने का लगाया आरोप

लखनऊ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर नारी शक्ति को कमजोर करने की साजिश करने का आरोप लगाया है। सोमवार को अपने सरकारी पर आवास पर मीडिया से वार्ता में उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि सपा के 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के खेल को जनता पूरी तरह समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति के लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनकल्याणकारी नीतियों के साथ खड़े हैं। विपक्ष के पास न कोई विजन है और न ही जनता के प्रति ईमानदारी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की मानसिकता सदैव महिला विरोधी रही है।

प्रधानमंत्री ने माताओं-बहनों को विधायी कार्यों में उचित भागीदारी देने के लिए महिला आरक्षण बिल रखा था, लेकिन विपक्ष ने इसे विफल करने का कुत्सित प्रयास किया। नारी शक्ति के अपमान और विपक्ष के रवैये के खिलाफ मंगलवार को 'जन आक्रोश रैली' निकाली जाएगी। उन्होंने कहा की भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक महिलाओं को सशक्त बनाया है। तुष्टिकरण और जातिवाद की राजनीति करने वाले दल अब हाशिए पर हैं।

सपा सरकार बनने पर फ्री मिलेगी 300 यूनिट बिजली, महिलाओं को 40 हजार पेंशन

● यूपी चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा वादा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वर्ष 2027 के चुनाव में पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। सपा प्रमुख ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय पर आयोजित बैठक में यह घोषणा की और महिलाओं को साल में 40 हजार रुपए पेंशन का अपना चुनावी वादा भी दोहराया। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र और संविधान विरोधी है। इसने प्रदेश की स्वास्थ्य शिक्षा, बिजली व्यवस्था सब चौपट कर दी है। सपा सरकार आने पर व्यवस्था में सुधार होगा और हर वर्ग को न्याय मिलेगा। वर्ष 2022 के विधान सभा चुनाव में भी सपा ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था।

स्मार्ट मीटर से बिजली ठगी का आरोप

सपा प्रमुख ने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर के नाम पर चल रही बिजली की ठगी के खिलाफ प्रदेश की जनता के गुस्से का मीटर हाई है, भाजपा के बिजली मीटर भी, ईवीएम मशीन की तरह हेराफेरी करते हैं। महंगे सिलिंडर और महंगी बिजली के बिल ही भाजपा का कनेक्शन सत्ता से काट देंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम दोहराते हुए वर्ष 2027 में अधिक से अधिक विधायक जिताना है। भाजपा की कुटिल चालों पर नजर रखनी होगी। वह झूठे आरोप लगाकर समाजवादियों को बदनाम करने की कोशिश करती है।

भाजपा सरकार पर अखिलेश का हमला

एक अन्य बयान में महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर कहा कि भाजपाई और उनके संगी-साथियों द्वारा अब नकली विरोध की शूटिंग कराई जा रही है। इसमें शामिल युवक-युवतियों का हम दोषी नहीं मानते, क्योंकि बेतहाशा बेरोजगारी के इस भाजपाई दौर में मजबूर होकर दो पैसों की उम्मीद में लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। भाजपा पहले गरीबी-मजबूरी पैदा करती है, फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर इस्तेमाल करती है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर से मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह तक स्केटिंग करते हुए जा रहे मोहम्मद तौहीद रजा, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद अमीरुल और मोहम्मद अली ने सपा प्रमुख से मुलाकात की। विधान सभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में स्केटिंग करते हुए सपा के पक्ष में प्रचार की इच्छा जताई।

असम विश्वविद्यालय सिलचर में 'आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत और उससे आगे' विषय पर 5 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमिः 20 अप्रैलः असम विश्वविद्यालय, सिलचर (AUS) के भौतिकी विभाग द्वारा पुणे स्थित इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA) तथा IUCAA सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी रिसर्च एंड डेवलपमेंट (ICARD) के सहयोग से आज 'आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत और उससे आगे' विषय पर पाँच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का औपचारिक शुभारंभ किया गया। यह कार्यशाला 20 से 24 अप्रैल 2026 तक भौतिकी विभाग के मेघनाद साहा कॉन्फ्रेंस रूम में आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान और उन्नत शोध-स्तरीय समझ के बीच की खाई को कम करना है, जिससे छात्रों एवं शोधार्थियों को आधुनिक भौतिकी की गहन अवधारणाओं की बेहतर समझ मिल सके। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता भौतिकी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो. अशोक कुमार सेन ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो. पैट्रिक दासगुप्ता उपस्थित रहे। मंच पर विभागाध्यक्ष प्रो. हिमाद्रि शेखर दास,

कार्यशाला समन्वयक एवं स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज के डीन प्रो. अत्रि देशमुख्य, तथा द्वष्ट समन्वयक डॉ. अप्रतिम गांगुली सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त आईएसआई कोलकाता की डॉ. भास्वती मंडल एवं आईआईटी गुवाहाटी के डॉ. सयान चक्रवर्ती सहित अन्य विशेषज्ञ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रतीकात्मक पौधारोपण के साथ की गई। इसके पश्चात उद्घाटन व्याख्यान में प्रो. अत्रि देशमुख्य ने कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह आयोजन विशेष रूप से उन विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है, जिन्हें सामान्य सापेक्षता जैसे जटिल विषयों पर व्यवस्थित प्रशिक्षण कम मिलता है। डॉ. अप्रतिम गांगुली ने IUCAA की शैक्षणिक भूमिका और ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करने के प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं प्रो. हिमाद्रि शेखर दास ने विभाग की शैक्षणिक उपलब्धियों और निरंतर आयोजित होने वाली अकादमिक गतिविधियों का उल्लेख किया। मुख्य अतिथि प्रो. पैट्रिक दासगुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में भी गणितीय समस्याओं को स्वयं हल करने की प्रक्रिया शोधकर्ताओं के बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

प्रतिभागियों की भागीदारी

इस कार्यशाला में कुल 61 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें पीएचडी शोधार्थी, एम.एससी. छात्र तथा स्नातक स्तर के विद्यार्थी शामिल हैं। प्रतिभागी असम एवं त्रिपुरा के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से आए हैं। उद्घाटन सत्र का संचालन सुश्री संचाली नाथ मजूमदार द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

नासिक TCS मामलाः मुख्य आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मुंबई। नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की बीपीओ इकाई में कथित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले की मुख्य आरोपित निदा खान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय ने निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने उसे गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से भी इनकार कर दिया है।

निदा खान को अदालत से नहीं मिली राहत

सोमवार को सुनवाई के दौरान निदा के वकील ने तर्क दिया था कि वह आठ सप्ताह की गर्भवती है और उस पर लगाए गए आरोपों में अधिकतम सजा तीन साल है, इसलिए उसे गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जानी चाहिए। अदालत ने अपराध की गंभीरता और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल उसे कोई भी राहत देने से मना कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

टीसीएस धर्मांतरण मामला

बता दें कि यह विवाद नासिक स्थित टीसीएस के बीपीओ सेंटर से शुरू हुआ था। एक 23 वर्षीय महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों ने उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। पीड़िता के अनुसार, उसे हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए मजबूर किया गया और शादी का झांसा देकर उसका यौन उत्पीड़न भी किया गया। पुलिस जांच के अनुसार, निदा खान इस पूरे प्रकरण की 'मास्टरमाइंड' मानी जा रही हैं। आरोप है कि उसने अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर युवतियों को निशाना बनाने और उन्हें धार्मिक रूप से प्रभावित करने का गिरोह चलाया। इस मामले में अब तक कई लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें से सात पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। निदा खान इकलौती

आरोपित है जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस का विशेष जांच दल (एसआईटी) उसकी तलाश में महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर रहा है। टीसीएस ने आरोपों के बाद निदा खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है और उसका सिस्टम एक्सेस भी ब्लॉक कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया है कि यह गिरोह 18 से 25 वर्ष की युवतियों को टारगेट करता था। पुलिस का मानना है कि निदा खान की गिरफ्तारी से इस धर्मांतरण सिंडिकेट के और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

नेपाल में भारतीय वाहनों पर कार्रवाई के बीच आई गुड न्यूज, गाड़ी मालिकों को मिलेगा फ्री पास

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नेपाल के अधिकारियों ने सीमावर्ती मधेश प्रांत में अवैध रूप से चल रहे भारतीय पंजीकृत वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। काठमांडू पोस्ट समाचार पत्र ने शुक्रवार को सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया कि अधिकारियों ने उन वाहनों के खिलाफ जांच अभियान शुरू किया है जो कस्टम प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना या अनुमति प्राप्त रहने की अवधि से अधिक समय तक चल रहे हैं।

भारतीय वाहनों के लिए एक दिन का फ्री पास

गृह मंत्रालय ने मधेश प्रांत के जिलों में चल रहे भारतीय पंजीकृत वाहनों की संख्या के बारे में डाटा मांगा है, जो बिहार से सटा हुआ है। जनकपुर जिले में पुलिस प्रवक्ता कमल थापा ने कहा, 'हमने नियमों का उल्लंघन करते हुए कस्टम क्लीयरेंस के बिना चल रहे किसी भी भारतीय पंजीकृत वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन को कड़ा किया है।' मुख्य कस्टम अधिकारी बिकाश राज राजक ने कहा कि निकटवर्ती सीमा बाजारों में जाने वाले भारतीय वाहनों को एक दिन का पास मुफ्त में जारी किया जाता है।

बिहार नहीं छोड़ूंगा... नीतीश कुमार का JDU MLAs को संदेश

सरकार के हर काम पर रखूंगा पैनी नजर

जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सोमवार को पार्टी विधायकों से कहा कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के एक सप्ताह बाद भी वे बिहार में विकास कार्यों पर नजर रखना जारी रखेंगे। कुमार ने 1, अणे मार्ग पर विधायक दल की एक बैठक को संबोधित किया, जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है और जहां जेडीयू सुप्रीमो, जो अब राज्यसभा सांसद हैं, लगभग दो दशकों से रह रहे हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जेडीयू एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हमारे पार्टी नेता ने कहा है कि संसद के उन सत्रों को छोड़कर जिनमें उनकी उपस्थिति आवश्यक होगी, वे अपना अधिकतम समय बिहार में बिताएंगे।

चार सदस्यीय समिति करेगी यूपी SI भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट की जांच, बोर्ड ने जारी की सूचना

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए दस्तावेजों व शारीरिक मानक की जांच चार सदस्यीय समिति करेगी। इस संदर्भ में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर को समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा संबंधित जिलों के पुलिस कमिश्नर, एसएसपी या एसपी द्वारा नामित डीएसपी, शिक्षा विभाग के राजपत्रित अधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित किसी एक चिकित्साधिकारी को समिति का सदस्य बनाया जाएगा। भर्ती बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के बाद शारीरिक मानक परीक्षण को लेकर समिति का निर्णय अंतिम होगा। सामान्य व अन्य पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक ऊंचाई 160 सेंटीमीटर मान्य होगी। वहीं सामान्य व अन्य पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए सीने का न्यूनतम माप 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर व फुलाने पर 82 सेंटीमीटर का माप होना चाहिए। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर व अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थियों की न्यूनतम शारीरिक ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही महिला अभ्यर्थियों का भार न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के किसानों को Yogi सरकार की बड़ी राहत, बिना ऑनलाइन पंजीकरण बेचें MSP पर गेहूं

सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उत्तर प्रदेश के किसान अब अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण के बिना सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं बेच सकते हैं। यह निर्णय खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए लिया गया है। बयान में स्पष्ट किया गया है कि किसानों की पहचान और उनकी फसलों के सत्यापन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिजिटल प्रणाली 'किसान रजिस्ट्री' अब अनिवार्य नहीं रहेगी।

डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों में पढ़े-लिखे लोगों का ठगा जाना चौंकाने वाला

● सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल ठगी के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पढ़े-लिखे लोग भी साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल ठगी के मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि पढ़े-लिखे लोग भी साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने सोमवार ये टिप्पणी उस वक्त की जब केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने विभिन्न विभागों में साइबर ठगी पर अंकुश के मामले में बैठकें चलने और मुद्दा विचाराधीन होने के आधार पर डिजिटल अरेस्ट के मामले की सुनवाई 12 मई तक टालने का अनुरोध किया।

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल ठगी पर जताई चिंता

डिजिटल अरेस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। सोमवार को सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि वह उस महिला को आधिकारिक रूप से जानते हैं, जिसके सेवानिवृति के स्प्रे लाभ धोखे से हड़प लिये गए। उसने अपनी सारी जमां पूंजी खो दी।

मामले की सुनवाई 12 मई तक स्थगित

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह चौकाने वाली बात है कि इतने पढ़े लिखे लोग भी इस तरह ठगी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने अटार्नी जनरल से इस पहलू पर भी ध्यान देने को कहा। अटार्नी जनरल ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इन सभी मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। बाद में कोर्ट ने अटार्नी जनरल का अनुरोध अनुरोध स्वीकार करते हुए डिजिटल अरेस्ट मामले की सुनवाई 12 मई तक स्थगित कर दी।